हरियाणा सरकार

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

2014 -15

अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

प्रकाशन संख्या–1119

हरियाणा सरकार

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

2014-15

अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा

श्री मनोहर लाल
मुख्य मंत्री, हरियाणा

कैप्टन अभिमन्यु
वित्त एवं योजना मंत्री, हरियाणा

श्री संजीव कौशल
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
योजना विभाग

श्री जगबीर सिंह दलाल
निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग,
हरियाणा

के कुशल नेतृत्व में

सन्देश

आंकड़ों के संग्रहण, संकलन एवम् विश्लेषण के क्षेत्र में अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग की राज्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

विभाग प्रत्येक वर्ष अन्य प्रकाशनों के साथ–साथ राज्य सांख्यिकीय सारांश तथा हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण जैसे महत्वपूर्ण प्रकाशन जारी करता है जो कि अन्य बजट दस्तावेजों के साथ प्रति वर्ष बजट सत्र के दौरान राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किये जाते हैं। इनके अतिरिक्त विभाग द्वारा राज्य की पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजनाऐं भी तैयार की जाती रही हैं।

यह अति सन्तोष और प्रसन्नता का विषय है कि अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा अपनी वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट जारी कर रहा है।

मैं आशा करता हूँ कि विभाग की यह वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट आंकड़ों के संग्रहण, संकलन एवं विश्लेषण तथा इनकी गुणवत्ता के प्रति हमें और ज्यादा प्रतिबद्ध बनाएगी।

चण्डीगढ़
दिनांक :18.12.2015

संजीव कौशल
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
योजना विभाग।

भूमिका

राज्य की आर्थिक स्थिति तथा महत्वपूर्ण सामाजिक पहलुओं विशेषकर क्षेत्रफल, जनसंख्या, कृषि, सिंचाई, वन, पशुपालन, बिजली, उद्योग, श्रम, सड़कें, स्वास्थ्य एवं शिक्षा इत्यादि से सम्बन्धित गुणवत्ता पूर्ण आंकड़ों के संग्रहण, संकलन एवं विश्लेषण करने तथा राज्य की पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाऐं तैयार करने तथा इनकी मोनिटरिंग करने में अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आंकड़ों के संग्रहण एवं सम्प्रेषण में होने वाले अनावश्यक विलम्ब को कम करने के लिए विभाग प्रयासरत है तथा इसके लिये सूचना एवं प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर विशेषतौर पर जोर दिया जा रहा है। व्याम टैक (सिस्टम इन्टिग्रेटर) विभाग के विभिन्न अनुभागों के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने का कार्य कर रहा है ताकि आंकड़ों के संकलन, सम्प्रेषण एवं विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया को हाई टैक किया जा सके।

मैं विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का उन द्वारा किऐ गऐ सराहनीय कार्यों के लिए आभार प्रकट करना चाहूँगा। विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट वार्षिक आधार पर तैयार की जाती है और प्रस्तुत संस्करण 2014–15 से सम्बन्धित है। मुझे आशा है कि विभाग की गतिविधियों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने में यह रिपोर्ट लाभदायक सिद्ध होगी।

पंचकूला
दिनांक : 22-12-2015

जगबीर सिंह दलाल, निदेशक
अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग,
हरियाणा।

हरियाणा राज्य की रूपरेखा

अलग राज्य के रूप में हरियाणा के गठन उपरान्त सरकार के प्रयासों और लोगों की कठिन मेहनत ने हरियाणा को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि अब इसकी गिनती देश के सर्वाधिक सम्पन राज्यों में होती है। राज्य ने कई क्षेत्रों में सराहनीय प्रगति की है। सभी गांवों को बिजली, पक्की सड़कें, पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाना एवं कृषि में नवीनतम तकनीक के उपयोग के साथ–साथ उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देना इत्यादि शामिल हैं। हरियाणा राज्य में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1966–67 में (आधार वर्ष 1960–61) 608/– रुपये थी जोकि बढ़कर वर्ष 2013–14 में (आधार वर्ष 2004–05) 1,33,427/– रुपये हो गई है। जनसंख्या घनत्व के लिहाज से भारत में हरियाणा का 12वां स्थान है। 2001 की जनगणना में यह घनत्व 478 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो कि 2011 में बढ़कर 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। जबकि जनसंख्या घनत्व का राष्ट्रीय आंकड़ा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था।

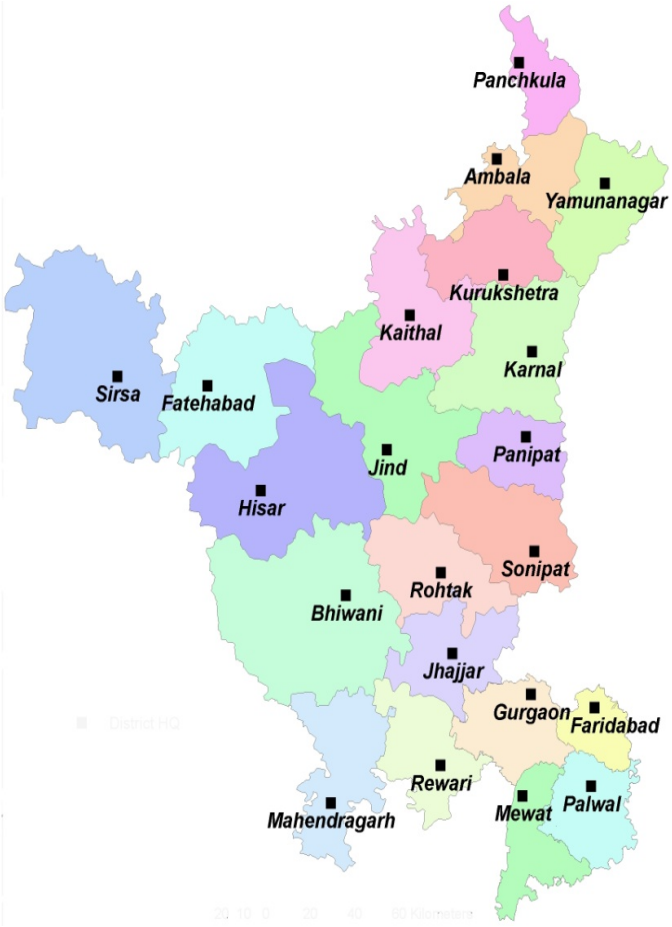

राज्य अर्थव्यवस्था एवं परिप्रेक्ष्य

हरियाणा राज्य ने इसके गठन के समय से ही अदभुत आर्थिक विकास किया है। अधिकांश वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर की तुलना में कहीं अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। यद्यपि हरियाणा भौगोलिक दृष्टि से छोटा सा राज्य है, परन्तु वर्ष 2013–14 के द्रुत अनुमानों (द्रु.अ.) के अनुसार राज्य ने राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भावों (2004–05) पर 3.5 प्रतिशत का योगदान दर्ज किया है। अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा राज्य की अर्थव्यवस्था का आर्थिक एवं सामाजिक विश्लेषण का कार्य करता है जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विवेचना निम्न प्रकार से है :–

राज्य सकल घरेलू उत्पाद

अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा हर वर्ष राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करता है। आंकड़ों की उपलब्धता को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों के राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान तीन विधियों नामतः उत्पादन, आय और व्यय विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। उत्पादन विधि कृषि एवं पशुधन क्षेत्र, वानिकी एवं लोगिंग, मत्स्य, खनन एवं उत्खनन और पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्रों के लिए; आय विधि अपंजीकृत विनिर्माण, परिवहन, भण्डारण एवं संचार, वित्त व्यवस्था, स्थावर सम्पदा एवं व्यवसायिक सेवाएं, व्यापार होटल एवं जलपान गृह, लोक प्रशासन एवं रक्षा तथा विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति क्षेत्रों के लिए तथा व्यय विधि निर्माण क्षेत्र के लिए अपनाई जा रही है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानों को चालू और स्थिर (2004–05) भावों पर **तालिका–1** में दर्शाया गया है।

तालिका–1 हरियाणा राज्य का सकल घरेलू उत्पाद

(रुपये करोड़)

योजना काल/वर्ष	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	
	चालू भावों पर	स्थिर भावों (2004–05) पर
11वीं पंचवर्षीय योजना		
2007–08	151595.90	126170.76
2008–09	182522.15	136477.94
2009–10	223600.25	152474.47
2010–11	260621.28	163770.20
2011–12	298688.33	176916.97
12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17)		
2012–13(अ.)	341351.16	186642.83
2013–14(द्रु.अ.)	388916.63	199656.83

अ.: अनन्तिम अनुमान, द्रु.अ.: द्रुत अनुमान

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

वर्ष 2012–13 के संशोधित अनुमानों के अनुसार चालू भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 3,41,351.16 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2013–14 (द्रु.अ.) में बढ़कर 3,88,916.63 करोड़ रुपये हो गया। स्थिर भावों (2004–05) पर वर्ष 2012–13 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 1,86,642.83 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2013–14 (द्रु.अ.) में 1,99,656.83 करोड़ रुपये हो गया।

11वीं व 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की स्थिर कीमतों (2004–05) पर विकास दर **तालिका–2 तथा आकृति–1** में दर्शाई गई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के दौरान कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों में 3.8 प्रतिशत तथा उद्योग क्षेत्र में 6.4 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम वृद्धि होने के बावजूद सेवा क्षेत्र में 12.2 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर के कारण ही राज्य अर्थव्यवस्था ने 8.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

तालिका–2 11वीं व 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	11वीं पंचवर्षीय योजना	12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17)	
	(2007–12)	2012–13 (अ.)	2013–14 (द्रु.अ.)
कृषि एवं डेयरी	3.8	–0.8	3.1
वानिकी एवं लोगिंग	2.4	3.0	3.5
मत्स्य	12.0	5.2	–5.3
कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र	**3.8**	**–0.6**	**3.1**
खनन एवं उत्खनन	–19.7	–19.0	14.9
विनिर्माण	6.5	4.5	2.2
बिजली, गैस एवं जल आपूर्ति	10.8	1.5	7.9
निर्माण	6.1	5.0	8.5
उद्योग क्षेत्र	**6.4**	**4.4**	**4.4**
परिवहन, संचार एवं व्यापार	12.9	6.5	5.2
वित्त एवं भू–सम्पदा	11.4	9.6	16.8
सार्वजनिक प्रशासन	9.5	5.8	9.6
अन्य सेवाएं	12.7	11.8	11.7
सामुदायिक एवं निजी सेवाएं	11.7	10.2	11.1
सेवा क्षेत्र	**12.2**	**7.9**	**9.4**
कुल सकल घरेलू उत्पाद	**8.8**	**5.5**	**7.0**

अ.: अनन्तिम अनुमान, द्रु.अ.: द्रुत अनुमान

स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष यानि 2012–13 के दौरान राज्य अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर धीमी पड़ गई। वर्ष 2012–13 में विकास दर के बहुत कम (5.5 प्रतिशत) होने का कारण कृषि एवं कृषि सहबद्ध क्षेत्रों (–0.6 प्रतिशत) में नकारात्मक वृद्धि, विनिर्माण (4.5 प्रतिशत), बिजली, गैस एवं जलापूर्ति (1.5 प्रतिशत), निर्माण (5.0 प्रतिशत) और सार्वजनिक प्रशासन (5.8 प्रतिशत) क्षेत्रों में हासिल की गई धीमी वृद्धि है।

आकृति–1 राज्य सकल घरेलू उत्पाद की क्षेत्रानुसार स्थिर (2004–05) कीमतों पर वृद्धि दर

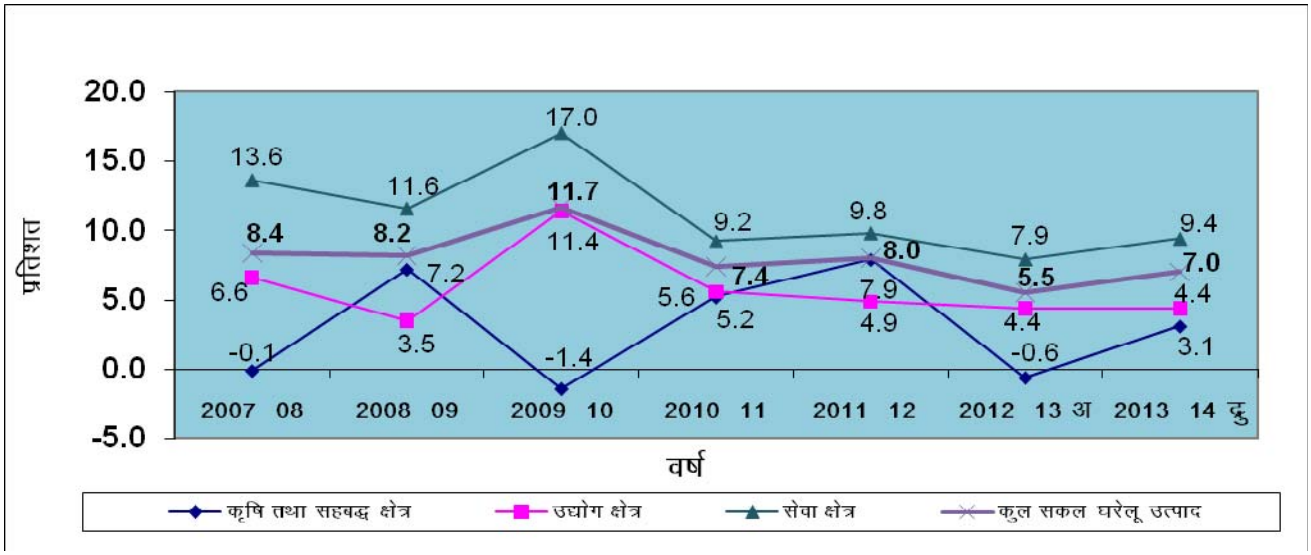

यद्यपि वर्ष 2013–14 में राज्य अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर ने धीरे–धीरे गति तो हासिल की लेकिन वित्त एवं भू–सम्पदा क्षेत्र (16.8 प्रतिशत), अन्य सेवाएं (11.7 प्रतिशत) और सार्वजनिक प्रशासन (9.6 प्रतिशत) की अधिक वृद्धि दर होने के बावजूद भी कृषि क्षेत्र (3.1 प्रतिशत), विनिर्माण (2.2 प्रतिशत) और परिवहन, संचार एवं व्यापार (5.2 प्रतिशत) क्षेत्रों में हासिल की गई कम वृद्धि के कारण राज्य की अर्थव्यस्था में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि ही दर्ज की जा सकी।

राज्य अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन

हरियाणा राज्य के गठन के समय राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण और कृषि आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरुआती वर्ष (1969–70) में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र (कृषि, वन एवं मत्स्य पालन) का स्थिर मूल्यों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान (60.7 प्रतिशत) था। इसके पश्चात सेवा (21.7 प्रतिशत) तथा उद्योग (17.6 प्रतिशत) क्षेत्र का योगदान था। इसके बाद राज्य अर्थव्यवस्था का विविधिकरण और आधुनिकीकरण की दिशा में झुकाव शुरू हुआ जो बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में सफलतापूर्वक जारी रहा।

चौथी और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य के 37 वर्षों (1969–70 से 2006–07) की अवधि के दौरान उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों ने कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की जिसके कारण

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अंश में वृद्धि हुई तथा कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का अंश कम हुआ। कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का अंश 1969–70 में 60.7 प्रतिशत से घटकर 2006–07 में 21.3 प्रतिशत रह गया जबकि उद्योग क्षेत्र का अंश 1969–70 में 17.6 प्रतिशत से बढ़कर 2006–07 में 32.1 प्रतिशत हो गया। सेवा क्षेत्र का अंश इसी अवधि के दौरान 21.7 प्रतिशत से बढ़कर 46.6 प्रतिशत हो गया।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तन की गति और अधिक त्वरित हुई। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेवा क्षेत्र में दर्ज की गई मजबूत वृद्धि के कारण राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011–12 में इसका अंश बढ़कर 54.5 प्रतिशत हो गया तथा कृषि एवं सहबद्ध गतिविधियों का अंश घटकर 16.8 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2012–13 और 2013–14 के दौरान भी सेवा क्षेत्र की विकास दर अन्य दो क्षेत्रों की विकास दर से ज्यादा थी। वर्ष 2013–14 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का अंश बढ़कर 57.0 प्रतिशत हो गया जबकि कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्रों का अंश घटकर 15.3 प्रतिशत रह गया **(आकृति–2)**। इस प्रकार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र का अंश लगातार घट रहा हैं तथा सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ रहा हैं जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था के बदलाव को अंकित करता है।

आकृति–2 राज्य सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्रानुसार संरचना में परिवर्तन

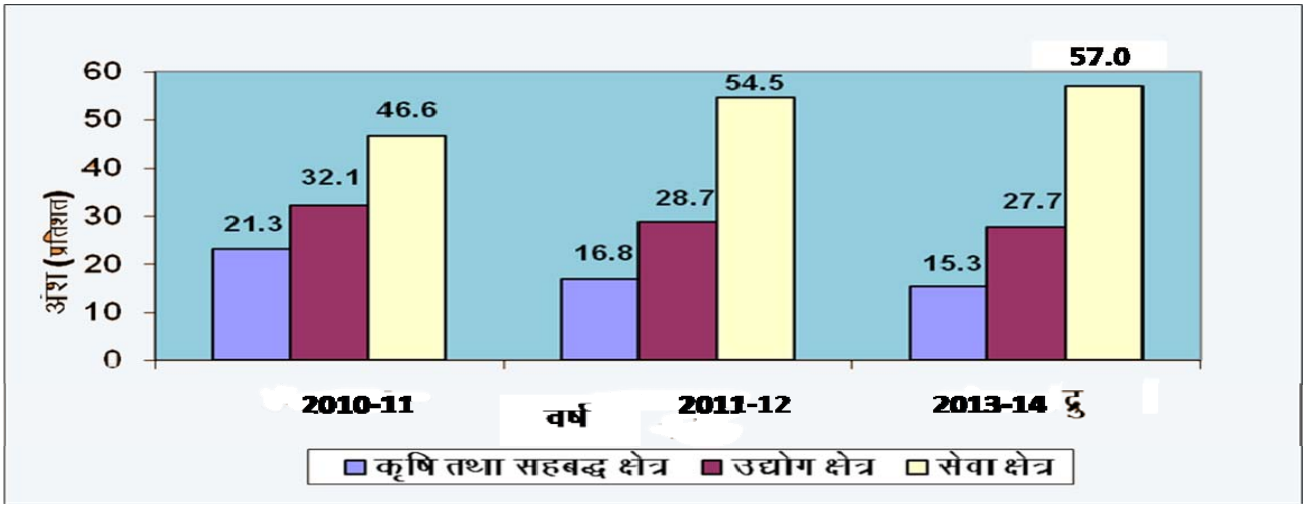

राज्य की प्रति व्यक्ति आय

प्रति व्यक्ति आय (प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद) राज्य तथा देश के आर्थिक विकास के साथ–साथ लोगों के माली हालात का आंकलन करने का एक महत्वपूर्ण सूचक है। प्रति व्यक्ति आय के अनुमान तैयार करने के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में से स्थाई पूंजी की खपत निकालने के उपरान्त निवल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की जनसंख्या से विभाजित किया जाता है।

$$\text{प्रति व्यक्ति आय} = \frac{\text{निवल राज्य घरेलू उत्पाद}}{\text{जनसंख्या}}$$

वर्ष 1966–67 के दौरान चालू भावों पर हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय केवल 608 रुपये थी। तब से हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय में कई गुणा वृद्धि हुई है। प्रचलित और स्थिर भावों (2004–05) पर 2007–08 से 2013–14 के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति आय को **आकृति–3** में प्रस्तुत किया गया है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर भावों (2004–05) पर 2012–13 में 64,052 रुपये से बढ़कर 2013–14 में 67,260 रुपये हो गई जोकि वर्ष 2013–14 में 5.0 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाती है। प्रचलित भावों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2012–13 में 1,19,833 रुपये से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 1,33,427 रुपये हो गई जो कि 2013–14 में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है।

आकृति–3 हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय

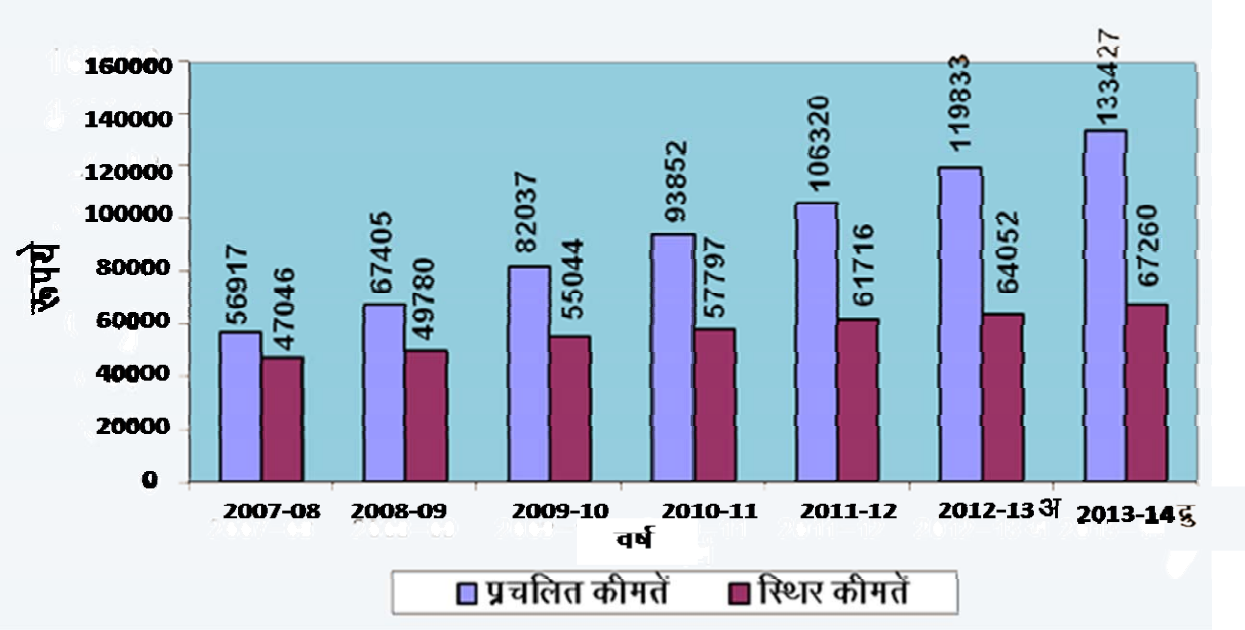

हरियाणा में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान भौतिक रूप में पुनः उत्पादन योग्य वस्तुओं के उत्पादकों की परिसम्पतियों जिनकी उपभोग की अनुमानित अवधि एक वर्ष या उससे अधिक हो, में बढ़ौतरी को दर्शाता है। इन अनुमानों का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि राज्य में सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में स्थाई परिसम्पतियों पर प्रति वर्ष कितना निवेश किया जा रहा है। यह अनुमान वर्ष के दौरान पूंजी परिसम्पतियों के सृजन के लिए किये गये व्यय को दर्शाता है। पूंजी निर्माण का एक विकासशील अर्थव्यवस्था में सर्वोपरि महत्व है। यह आर्थिक विकास को निर्धारित करने का कार्य करता है। अर्थ एवं सांख्यिकीय विशलेषण विभाग, हरियाणा प्रचलित एवं स्थिर (2004–05) भावों पर राज्य में सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान तैयार करता है जिसे **(तालिका–3)** में दिखाया गया है।

तालिका–3 राज्य में सकल स्थाई पूंजी निर्माण

(रुपये करोड़)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2004-05) भावों पर
2004-05	14520	14520
2005-06	16631	16128
2006-07	20264	18439
2007-08	26463	22305
2008-09	31652	24708
2009-10	36023	26618
2010-11	42616	30090
2011-12	47948	30958
2012-13	53158	32041

प्रचलित भावों पर राज्य में वर्ष 2012–13 के अनुमान अनुसार 53158 करोड़ रुपये के सकल स्थाई पूंजी निर्माण का आंकलन किया गया। इसी तरह स्थिर (2004–05) भावों पर सकल स्थाई पूंजी निर्माण वर्ष 2012–13 में 32041 करोड़ रुपये था।

ओद्यौगिक उत्पादन सूचकांक

किसी भी अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में औद्योगिकरण की एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह राज्य की आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के साथ–2 उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि होने से औद्योगिक क्षेत्र के राज्य घरेलू उत्पाद के अंशदान में वृद्धि होती है।

एक चयन किए गए आधार वर्ष पर एक समय अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन की प्रवृति के अध्ययन के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण सूचकांकों में से एक है। इस समय राज्य में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, अर्थ और सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा द्वारा आधार वर्ष 2004–05 पर तैयार किया जा रहा है।

राज्य का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2004–05) वर्ष 2012–13 में 179.3 से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 184.0 हो गया जिसमें गत वर्ष की तुलना में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। इसमें विनिर्माण क्षेत्र का सूचकांक वर्ष 2012–13 के 173.6 से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 177.8 हो गया जो 2.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। विद्युत क्षेत्र का सूचकांक गत वर्ष की तुलना में 3.8 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है, क्योंकि यह वर्ष 2012–13 के 243.5 से बढ़कर वर्ष 2013–14 में 252.7 हो गया। वर्ष 2012–13 की तुलना में वर्ष 2013–14 मे औद्योगिक आधारभूत पदार्थ के सूचकांक में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि, औद्योगिक पूंजीगत पदार्थ के सूचकांक में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि, औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थ के सूचकांक में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि औद्योगिक मध्यवर्ती पदार्थ के सूचकांक में 9.8 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई **(तालिका–4)।**

तालिका–4 हरियाणा में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक

(आधार वर्ष 2004–05=100)

औद्योगिक समूह	सूचकांक							
	2006-07	**2007-08**	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14 (अ)**
विनिर्माण	118.6 (10.4)	126.3 (6.4)	129.4 (2.5)	144.8 (12.0)	159.7 (10.3)	165.9 (3.9)	173.6 (4.6)	177.8 (2.4)
विद्युत	128.5 (10.2)	132.9 (3.5)	154.8 (16.5)	176.2 (13.8)	181.0 (2.7)	230.4 (27.3)	243.5 (5.7)	252.7 (3.8)
औद्योगिक आधारभूत पदार्थ	113.8 (6.6)	119.4 (4.9)	133.3 (11.7)	150.8 (13.1)	157.0 (4.1)	186.4 (18.7)	212.2 (13.8)	214.5 (1.1)
औद्योगिक पूंजीगत पदार्थ	131.6 (22.8)	147.8 (12.3)	143.7 (-2.8)	175.2 (21.9)	210.8 (20.3)	203.5 (-3.4)	189.9 (-6.7)	204.8 (7.8)
औद्योगिक मध्यवर्ती पदार्थ	114.6 (6.2)	122.3 (6.7)	127.1 (3.9)	141.5 (11.3)	148.5 (5.0)	162.2 (9.2)	173.8 (7.2)	156.7 (-9.8)
औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थ	118.8 (8.1)	121.7 (2.4)	125.8 (3.3)	132.4 (5.3)	143.0 (8.0)	148.1 (3.6)	156.0 (5.3)	170.4 (9.2)
क) उपभोक्ता टिकाऊ पदार्थ	125.2 (12.8)	129.2 (3.1)	132.0 (2.2)	138.6 (5.0)	158.4 (14.3)	173.9 (9.8)	179.0 (2.9)	187.1 (4.5)
ख) उपभोक्ता गैर– टिकाऊ पदार्थ	114.4 (4.8)	116.5 (1.9)	121.5 (4.2)	128.1 (5.4)	132.3 (3.2)	130.2 (-1.6)	140.0 (7.5)	158.9 (13.5)
सामान्य औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	**119.4 (10.4)**	**126.8 (6.2)**	**131.5 (3.7)**	**147.4 (12.1)**	**161.5 (9.5)**	**171.2 (6.0)**	**179.3 (4.7)**	**184.0 (2.6)**

अः अनन्तिम, स्त्रोतः अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा।

कीमत सूचकांक

वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि, जिसे मुद्रास्फीति के रुप में मापते हैं, अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण निर्धारक है। मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक के साथ-साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मापते हैं। थोक मूल्य सूचकांक थोक बाजार में वस्तुओं की थोक कीमतों पर आधारित होते हैं जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उन कीमतों पर आधारित हैं जिन पर उपभोक्ता स्थानीय बाजार में वस्तुओं को खुदरा भावों पर खरीदता है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि, विशेषतयाः गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली जनसंख्या पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। मुद्रास्फीति में तीन से चार अंक तक की वृद्धि अर्थव्यवस्था में उत्पादन को प्रोत्साहित करने वाली मानी गई है और यह उपभोग को हतोत्साहित नहीं करती। राज्य में कीमतों की स्थिति का आंकलन करने के लिए अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा राज्य के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से साप्ताहिक/मासिक आधार पर आवश्यक वस्तुओं के थोक व खुदरा भाव एकत्रित करता है और थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) व श्रमिक वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करता है।

श्रमिक वर्ग के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष के संदर्भ में एक निश्चित अवधि के दौरान एक औसत श्रमिक वर्ग के परिवार द्वारा उपभोग की गई निश्चित वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों की प्रवृति को दर्शाता है। यह छः केन्द्रों नामतः सूरजपूर पिन्जौर, पानीपत, सोनीपत, भिवानी, हिसार और बहादुरगढ़

के मासिक भारित औसत सूचकांको को ध्यान में रखकर संकलित किया जा रहा है। राज्य के श्रमिक वर्ग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2010 से वर्ष 2014 तक को **आकृति–4** में प्रस्तुत किया गया है। श्रमिक वर्ग के लिये वार्षिक औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हरियाणा (आधार वर्ष 1982=100) में वर्ष 2013 में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2014 में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

आकृति–4 हरियाणा का श्रमिक वर्ग के लिये वर्ष–वार और केन्द्र–वार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

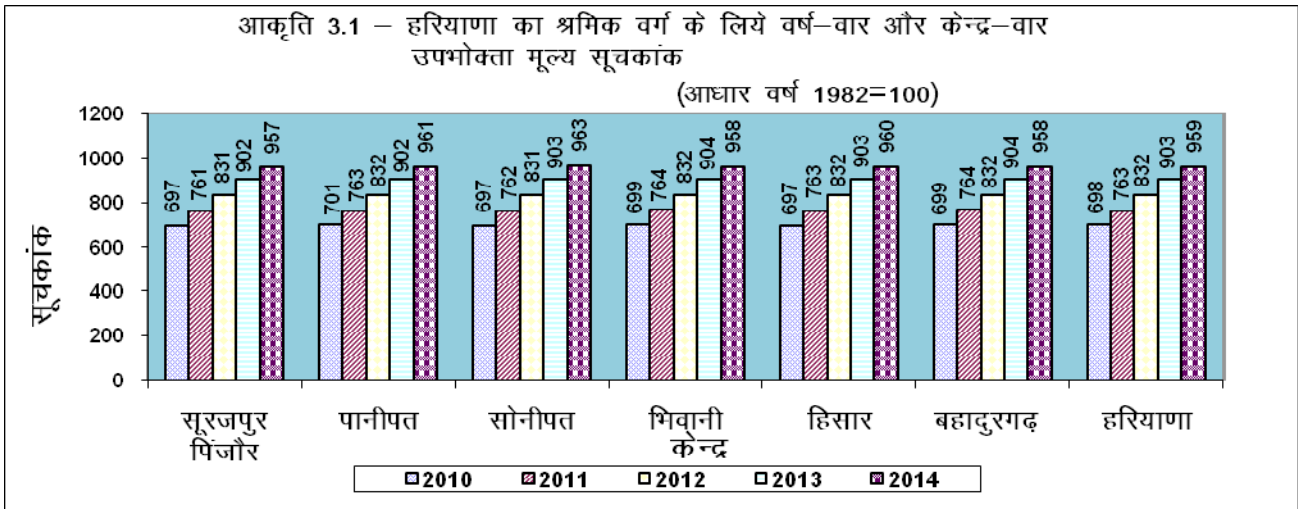

राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना एवं वर्ष 2014–15 की वार्षिक योजना

सभी गांवों को शुद्ध पेयजल, बिजली उपलब्ध कराने एवं पक्की सड़कों से जोड़ने में हरियाणा देश में पहला राज्य है। अब इन सभी सुविधाओं के और अधिक विकास के लिए निवेश की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त राज्य की अर्थव्यवस्था के विस्तार एवं विकास को कायम रखने के लिए नये ढ़ांचे के निर्माण तथा पुराने आधारभूत ढ़ांचे की उन्नति के लिए गंभीर प्रयासों की भी आवश्यकता है।

राज्य की 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है तथा यह सब 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान भी जारी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 'अधिक तीव्र, समावेशी तथा टिकाऊ विकास' के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा शुद्ध योजना परिव्यय 90,000.00 करोड़ रुपये रखा गया है। यह परिव्यय 11वीं पंचवर्षीय योजना के परिव्यय की तुलना में 157 प्रतिशत अधिक है।

वार्षिक योजना 2014–15 को योजना आयोग, भारत सरकार से अनुमोदित करवाने के लिए राज्यों के सचिवों एवं सलाहकारों के साथ बैठकों का आयोजन किया गया। योजना आयोग, भारत सरकार से वर्ष 2014–15 की राज्य की वार्षिक योजना के लिए 32731.29 करोड़ रुपये अनुमोदित करवाए। इस परिव्यय में 10158.80 करोड़ रुपये राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा 1052.34 करोड़ रुपये स्थानीय निकायों के लिए

सम्मिलित हैं जोकि उनके स्वयं के स्त्रोतों से जुटाए जाएगें। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों एवं स्थानीय निकायों के परिव्यय के अतिरिक्त राज्य का शुद्ध योजना परिव्यय 21520.15 करोड़ रुपये रखा गया था। राज्य के स्त्रोतों का पुनः निर्धारण करते हुए राज्य का शुद्ध योजना परिव्यय 21327.65 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया।

आकृति–5 हरियाणा की संशोधित वार्षिक योजना 2014–15 का क्षेत्रवार आबंटन (रुपये करोड़ में)

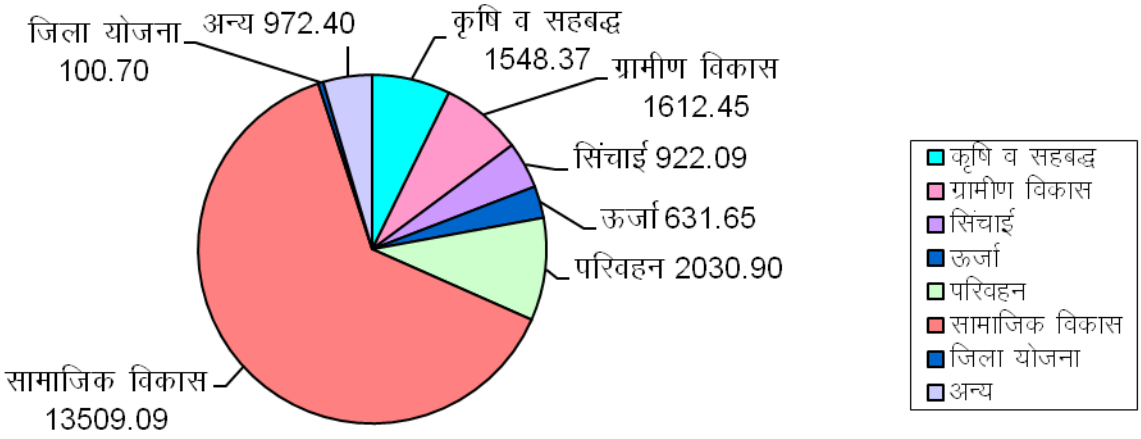

संशोधित परिव्यय के आबंटन के दौरान शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, जलापूर्ति, शहरी विकास तथा स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। राज्य की वार्षिक योजना 2014–15 के संशोधित परिव्यय में से 13509.09 करोड़ रुपये (63.34 प्रतिशत) की राशि सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए रखी गई। इस परिव्यय में से 4517.78 करोड़ रुपये (21.78 प्रतिशत) शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा 2940.12 करोड़ रुपये (13.78 प्रतिशत), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता 1220.00 करोड़ रुपये (5.72 प्रतिशत), जलापूर्ति 1753.61 करोड़ रुपये (0.82 प्रतिशत), शहरी विकास 1442.28 करोड़ रुपये (6.76 प्रतिशत), स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा, शिक्षा, आयुर्वेद तथा कर्मचारी राज्य बीमा के लिए तथा शेष 1635.10 करोड़ रुपये महिला एवं बाल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण, नगरीय एवं नियोजन, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा आवासीय क्षेत्रों आदि के लिए रखे गये।

आधारभूत संरचना के विकास को गति देने के लिए संशोधित वार्षिक योजना 2014–15 में 4125.64 करोड़ रुपये (19.34 प्रतिशत) सिंचाई, बिजली, सड़क तथा सड़क परिवहन तथा आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के लिए आबंटित किए गए। आधारभूत सरंचना के विकास के अन्तर्गत यातायात क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देते हुए इसके लिए 2030.90 करोड़ रुपये (9.52 प्रतिशत) आबंटित किए गए। जिसमें से 197.40 करोड़ रुपये राज्य परिवहन की वर्तमान बसों की संख्या व लोक परिवहन सेवाओं की बढ़ती मांग के अन्तर को पूरा करने के लिये रखे गये। दूसरी प्राथमिकता सिंचाई व बाढ़ नियन्त्रण के लिए 922.09 करोड़ रुपये (4.32 प्रतिशत) उपलब्ध कराए गए। संशोधित वार्षिक योजना 2014–15 में बिजली के लिए 631.65 करोड़ रुपये (2.96 प्रतिशत) रखे गए। आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के लिए 541.00 करोड़ रुपये (2.54 प्रतिशत) रखे गए।

कृषि व सहबद्ध क्षेत्रों के लिए संशोधित वार्षिक योजना 2014–15 में 1548.37 करोड़ रुपये (7.26 प्रतिशत) आबंटित किए गए। संशोधित वार्षिक योजना 2014–15 में ग्रामीण विकास क्षेत्र (जिसमें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तथा ग्रामीण आधारभूत ढांचे के सुधार हेतु अन्य कार्य सम्मिलित है) के लिये 1612.45 करोड़ रुपये (7.56 प्रतिशत) आबंटित किए गए। इस क्षेत्र में 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी गई जिसके लिये संशोधित वार्षिक योजना 2014–15 में 487.53 करोड़ रुपये (2.28 प्रतिशत) रखे गए। संशोधित वार्षिक योजना 2014–15 में पिछड़े क्षेत्र मेवात तथा अम्बाला, पंचकूला व यमूनानगर जिले के पर्वतीय एवं अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु मेवात विकास बोर्ड तथा शिवालिक विकास बोर्ड को 38.00 करोड़ रुपये (0.18 प्रतिशत) की राशि आबंटित की गई। उद्योगों के लिये संशोधित वार्षिक योजना 2014–15 में 102.10 करोड़ रुपये रखे गये। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के लिये संशोधित वार्षिक योजना 2014–15 में 37.20 करोड़ रुपये रखे गए। वर्तमान पर्यटक स्थलों में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिये संशोधित वार्षिक योजना 2014–15 में 31.50 करोड़ रुपये रखे गये। संशोधित वार्षिक योजना 2014–15 में जिला योजना के लिये 100.70 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया जो स्थानीय विकास कार्यों पर उपयोग होगें। सामान्य सेवाओं के लिये संशोधित वार्षिक योजना 2014–15 में 205.51 करोड़ रुपये रखे गये।

***

अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा के वर्ष 2014-15 के कार्यों की समीक्षा

यह विभाग राज्य में विभिन्न विकास कार्यक्रमों के नियोजन, नीति निर्धारण एवं प्रशासन हेतु विभिन्न प्रकार के अभीष्ट आंकड़ों का संग्रहण/संकलन एवं विश्लेशण करता है। राज्य की पंचवर्षीय तथा वार्षिक योजना तैयार करने तथा आर्थिक एवं सांख्यिकीय मामलों मे राज्य सरकार को परामर्श देने का कार्य भी विभाग द्वारा किया जाता है।

हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण, 2014–15 जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति की वस्तु स्थिति दर्शाई जाती है, को तैयार कर बजट सत्र के दौरान सोफ्टकोपी (सीडी) में हरियाणा विधान सभा में प्रस्तुत किया गया।

हरियाणा सांख्यिकीय सारांश, 2013–14 जिसमें राज्य के विभिन्न सामाजिक–आर्थिक पहलुओं पर विस्तृत आंकड़ें दिये जाते हैं, को तैयार कर बजट सत्र के दौरान हरियाणा विधान सभा सदस्यों को सोफ्टकोपी (सीडी) में प्रस्तुत किया गया।

विभाग द्वारा 31–3–2013 की स्थितिनुसार हरियाणा सरकार के अधीन अमले की गणना का कार्य किया गया व कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के अनुसार वर्गीकरण सम्बन्धी कार्ड जारी किया गया।

श्रमिक वर्ग के मासिक उपभोक्ता कीमत सूचकांक नियमित तौर पर तैयार करके हरियाणा गजट में प्रकाशित किये गये। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण) तथा 20 चयनित कृषि वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक मासिक आधार पर पर तैयार किये गए।

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद, निवल राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय के अनुमान प्रचलित तथा स्थिर (2004–05) दोनों भावों पर वर्ष 2012–13 के लिए तैयार किये गए। वर्ष 2013–14 के द्रुत अनुमान भी प्रचलित तथा स्थिर (2004–05) दोनों भावों पर तैयार किये गए।

राज्य के जिला–वार सकल राज्य घरेलू उत्पाद, निवल राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय के अनुमान वर्ष 2011–12 प्रचलित तथा स्थिर (2004–05) दोनों भावों पर संशोधित किये गए। वर्ष 2004–05 से 2012–13 तक प्रचलित तथा स्थिर (2004–05) दोनों भावों पर राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमानों सम्बन्धी रिर्पोट प्रकाशित करवाई गई ।

राज्य में वर्ष 2012–13 में सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान प्रचलित तथा स्थिर (2004–05) दोनों भावों पर तैयार किये गये।

हरियाणा सरकार के बजट 2014–15 का आर्थिक एवं प्रयोजनवार वर्गीकरण तथा राज्यों के 2013–14 के वित्त का विष्लेषण नामक रिर्पोटों को तैयार किया गया।

हरियाणा की नगरपालिकाओं/परिषदों/निगमों के बजटों का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण वर्ष 2012–13 से सम्बन्धित रिपोर्ट तैयार की गई।

वर्ष 2012–13 की कृषि लेखा तथा कृषक परिवार बजट सम्बन्धी अध्ययन रिपोर्टें तैयार की गई व वर्ष 2013–14 से सम्बन्धित उक्त रिपोर्टों को तैयार करने का कार्य प्रगति पर रहा। राज्य में विभिन्न फसलों के अधीन क्षेत्र, पैदावार व उपज सम्बन्धी सूचकांक तैयार किये गये।

औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार वार्षिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 2005–06 से 2013–14 से सम्बन्धित एक रिपोर्ट तैयार की गई।

राष्ट्रीय भवन संगठन से सम्बन्धित आंकड़े एकत्रित करने के लिए सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर रहा।

वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य की छठवीं आर्थिक गणना के भरे हुए प्रपत्रों की स्कैनिंग तथा 8 या इससे अधिक वर्कस वाले उद्यमों/इकाइयों की डारेक्ट्री हेतू 6सी प्रपत्रों की डाटा एन्ट्री का कार्य प्रगति पर रहा। इसके अतिरिक्त छठवीं आर्थिक गणना के अन्तिम परिणाम जारी किये गए।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 71वें दौर के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण किया गया व 72वें दौर के सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर रहा।

तीन जिलों में प्रशिक्षण कैम्प आयोजित किये गए जिनमें विभिन्न विभागों के जिलों मे कार्यरत 109 कर्मचारियों को प्राथमिक सांख्यिकी सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। विभाग के 96 अधिकारियों/कर्मचारियों ने राज्य व भारत सरकार के विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

राज्य की वार्षिक योजना 2015–16 तैयार की गई। वर्ष 2014–15 की वार्षिक योजना की कार्यान्वयन/मोनिटरिंग सम्बन्धी कार्य भी प्रगति पर रहे। जिला योजना स्कीम के तहत राज्य के सभी जिलों को विभिन्न विकास कार्यों हेतु 30,750.00 लाख रुपए की राशि आबंटित/जारी की गई।

राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए चयनित 2 संस्थाओं को 8 मूल्यांकन अध्ययन/ अनुसन्धान कार्य प्रदान किये गए। इसके अतिरिक्त राज्य मे 20–सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन से सम्बन्धित मासिक तथा त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों की नियमित रूप से समीक्षा की गई तथा वांछित सूचना भारत सरकार को भेजी गई।

सभी जिलों में वर्ष 2012–13 के जिला सांख्यिकीय सारांश, सामाजिक–आर्थिक समीक्षा तथा नगरपालिका वार्षिक पुस्तकें तैयार की गई। जिला सांख्यिकीय कार्यालय अपने जिलों से सम्बन्धित सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित कर मुख्यालय को भेजने के कार्यकलापों में व्यस्त रहे तथा योजना कार्यालय अपने जिलों की योजनाएं तैयार करने तथा इस स्कीम के अन्तर्गत क्रियान्वयन एजैंसियों को राशि जारी करने सम्बन्धी कार्यों में व्यस्त रहे।

संजीव कौशल
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
योजना विभाग।

चण्डीगढ़
दिनांक :18.12.2015

अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 2014–15

अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा राज्य के सभी विभागों की सांख्यिकीय गतिविधियों को व्यवस्थित करने हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप मे कार्य करता है। यह विभाग हरियाणा सरकार के योजना विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन कार्य करता है। इसके मुख्य कार्य निम्न प्रकार वर्णित हैं :–

(क) राज्य के विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक पहलुओं से सम्बन्धित आंकड़ों का संग्रह/संकलन करना तथा उनका विश्लेषण करना;

(ख) राज्य की योजना एवं विकास कार्यक्रमों के निरूपण हेतु अपेक्षित आंकड़ें जुटाना;

(ग) राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करके इसे बजट सत्र के दौरान राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करना;

(घ) राज्य सरकार को आर्थिक एवं सांख्यिकीय मसलों पर परामर्श देना;

(ड़) विकास योजनाओं/परियोजनाओं/स्कीमों का मूल्याकंन करना;

(च) राज्य की पंचवर्षीय योजना/वार्षिक योजनाऐं बनाना तथा उनकी मोनिटरिंग सम्बन्धी कार्य करना;

(छ) राज्य का वार्षिक योजनागत बजट तैयार करना जिसका अनुमोदन राज्य विधान सभा द्वारा बजट सत्र के दौरान किया जाता है;

(ज) जिला योजना के अन्तर्गत जिला योजनाऐं बनाना तथा उनके अन्तर्गत् विकास कार्यों हेतु राशि आबटिंत/जारी करना;

(झ) 20–सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति रिर्पोटों की समीक्षा करना;

(ञ) केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार तथा अन्य राज्यों के अर्थ एवं सांख्यिकीय विभागों के साथ सम्पर्क करके कार्य करना;

(ट) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सांख्यिकीय कार्यों का समन्वय करना;

(ठ) विभिन्न विभागों की मानवशक्ति एवं रोजगार गतिविधियों का समन्वय करना तथा मानवशक्ति एवं रोजगार प्रदान करने वाली परियोजनाओं का अध्ययन करना इत्यादि।

यह मुख्यतः एक अनुसंधान विभाग है जो कि समय–समय पर नियमित तथा तदर्थ आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण/अध्ययन करता है। इस विभाग द्वारा हरियाणा सांख्यिकीय सारांश, हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण, राज्य के बजट का आर्थिक एवं प्रयोजनवार वर्गीकरण, राज्य की नगरपालिकाओं/परिषदों/निगमों के बजटों का आर्थिक तथा कार्यात्मक वर्गीकरण, कृषि लेखा तथा कृषकों के परिवार बजट से सम्बन्धित कई वार्षिक प्रकाशन नियमित आधार पर तैयार करके मुद्रित करवाए जाते हैं। विभाग द्वारा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद, निवल राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय के अनुमान हर वर्ष तैयार करने के साथ–साथ कीमत, औद्योगिक उत्पादन एवं कृषि सम्बन्धी सूचकांक तैयार किये जाते हैं। इस विभाग के कोई भौतिक लक्ष्य अथवा उपलब्धियाँ नहीं होती हैं।

इस विभाग में सांख्यिकीय तथा योजना प्रभागों के अन्तर्गत क्रमशः निम्नलिखित अनुभाग कार्य कर रहे हैं :–

(क) सांख्यिकीय विंग

1 संकलन

2 कीमत

3 राज्य आय

4 स्थाई पूंजी निर्माण

5 लोक वित्त

6 क्षेत्रीय लेखा

7 कृषि

8 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण एवं सारणीकरण

9 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

10 प्रशिक्षण

11 आर्थिक सर्वेक्षण

12 आई. टी.

13 तदर्थ सर्वेक्षण

14 छठी आर्थिक गणना

15 स्टेट स्ट्रैटेजिक सटैटस्टीकल प्रोजेक्ट

(ख) योजना विंग

16 योजना निरूपण

17 योजना मोनिटरिंग

18 योजना मूल्यांकन

19 जिला योजना

20 मानवशक्ति तथा रोजगार समन्वय

21 प्रदर्शन प्रबन्धन सैल

इसके अतिरिक्त प्रशासनिक मामलों हेतु स्थापना/प्रशासन शाखा एवं लेखा सम्बन्धी मामलों के लिए लेखा शाखा कार्य कर रहे हैं।

वर्ष 2014–15 के दौरान विभिन्न अनुभागों द्वारा किये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

(क) सांख्यिकीय विंग

1. संकलन अनुभाग

यह अनुभाग मुख्यतः राज्य के विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं पर आंकड़ों का संग्रह तथा संकलन करके इनका नियमित रूप से प्रकाशन करवाता है।

इस अनुभाग द्वारा प्रकाशित प्रकाशनों से विभिन्न विभागों/विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों/अनुसंधान कर्ताओं के दिन प्रतिदिन के आंकड़ों की सांख्यिकीय आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाता है। राज्य सांख्यिकीय सारांश को तैयार करना विभाग का एक वार्षिक कार्य है। तदानुसार वर्ष 2014–15 में वर्ष 2013–14 के सांख्यिकीय सारांश को तैयार किया गया। इस दस्तावेज को बजट सत्र के दौरान अन्य बजट प्रलेखों के साथ सोफ्टकोपी (सी.डी.) के रूप में राज्य विधानसभा सदस्यों को प्रस्तुत किया गया। इस दस्तावेज में सभी महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक पहलुओं विशेषकर क्षेत्रफल, जनसंख्या, कृषि, सिंचाई, बिजली, उद्योग, श्रम तथा रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सहकारिता, लोक वित्त, कीमत, राज्य आय आदि के आंकड़ों का समावेश किया जाता है। ये आंकड़े राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति को जानने में अत्यधिक सहायक सिद्ध होते हैं। यह इस विभाग का महत्वपूर्ण संदर्भ दस्तावेज है, जिसकी मांग गत वर्षो की तुलना में बढ़ती जा रही है।

यह अनुभाग वर्ष 1967 से प्रति वर्ष कर्मचारी वर्ग की गणना से सम्बन्धित आवश्यक सूचना एकत्रित कर रहा है। इस सूचना का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा समय समय पर कर्मचारियों के हित में नीति निर्धारण हेतु तथा कर्मचारियों को अन्य वित्तिय सुविधाएं प्रदान करने सम्बन्धी निर्णय लेने में किया जाता है। संदर्भाधीन अवधि के दौरान हरियाणा सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में कार्यरत अमला के आंकड़ें 31 मार्च, 2013 की स्थितिनुसार संकलित करके कार्ड मुद्रित करवाया गया तथा 31 मार्च, 2014 से सम्बन्धित अमला के आंकड़ों का संग्रह एवं संकलन का कार्य प्रगति पर रहा।

इसके अतिरिक्त कृषि श्रमिक मजदूरी तथा ग्रामीण खुदरा भावों की सूचना मास फरवरी, 2014 से जनवरी, 2015 तक एकत्रित तथा संकलित करके कृषि मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजी गई।

2. कीमत अनुभाग

यह अनुभाग साप्ताहिक खुदरा भाव, पाक्षिक ग्रामीण भाव, 20 चयनित कृषि वस्तुओं के थोक भाव तथा त्रैमासिक मकान किराया सर्वेक्षण से सम्बन्धित सूचना एकत्रित करता है व 20 चयनित कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक, खुदरा भाव (ग्रामीण) सूचकांक तथा श्रमिक वर्ग उपभोक्ता कीमत सूचकांक तैयार करता है।

रिपोर्टाधीन अवधि में, राज्य के छः केन्द्रों नामतः भिवानी, हिसार, सोनीपत, सूरजपूर–पिंजौर, बहादुरगढ़ तथा पानीपत की सूचना संकलित करके मास फरवरी, 2014 से जनवरी, 2015 तक के श्रमिक वर्ग उपभोक्ता

कीमत सूचकांक (आधार वर्ष 1982=100) तैयार करके अधिसूचित किये गए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की हैसियत से जनवरी, 2014 से जून, 2014 तक तथा जुलाई, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक के छः माही श्रमिक वर्ग उपभोक्ता कीमत सूचकांक उक्त छः चुने हुए केन्द्रों का तैयार करके इनकी गजट अधिसूचना जारी की गई तथा इनकी एक प्रति श्रम विभाग, हरियाणा को प्रेषित की गई।

मास फरवरी, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक के 20 चयनित कृषि वस्तुओं के थोक भावों के सूचकांक (आधार वर्ष 1980–81=100) तैयार किये गए।

इसके अतिरिक्त अनुभाग द्वारा ग्रामीण खुदरा भावों के मास मार्च, 2014 से जनवरी, 2015 तक के सूचकांक तैयार किये गए।

त्रैमासिक मकान किराया सर्वेक्षण से सम्बन्धित तिमाही मार्च, जून, सितम्बर, तथा दिसम्बर, 2014 की प्राप्त भरी हुई अनुसूचियों की छानबीन करके मकान किराये का सूचकांक तैयार किया गया।

कीमत मोनिटरिंग सैल के लिए मास अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 तक की कीमतों की समीक्षा तैयार करके निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा को भेजी गई।

3. राज्य आय अनुभाग

यह अनुभाग राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय के अनुमान प्रचलित तथा स्थिर भावों पर नियमित तौर पर तैयार करता है। ये अनुमान राज्य के आर्थिक विकास को मापने के लिए महत्वपूर्ण सूचकांक होते हैं ।

इस अनुभाग द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान, राज्य के सकल एवं निवल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय के अनुमान प्रचलित तथा स्थिर (2004–05) दोनों भावों पर वर्ष 2012–13 (संशोधित), वर्ष 2013–14 (द्रुत) तथा 2014–15 (अग्रिम) तैयार किये गए।

इसके अतिरिक्त राज्य के जिला स्तरीय सकल एवं निवल राज्य घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय के अनुमान वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक प्रचलित तथा स्थिर (2004–05) भावों पर संशोधित किये गए। इसके अतिरिक्त उक्त अनुमान वर्ष 2010–11 (अनन्तिम) एवं वर्ष 2011–12 (द्रुत) प्रचलित तथा स्थिर (2004–05) भावों पर तैयार किये गए।

4. स्थाई पूंजी निर्माण

स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान पूंजी परिसम्पतियों के सृजन के लिए किये गये व्यय को दर्शाता है। यह अनुभाग प्रति वर्ष प्रचलित एवं स्थिर (2004–05) भावों पर राज्य में सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान तैयार करता है। वर्ष 2014–15 के दौरान इस अनुभाग द्वारा वर्ष 2012–13 के राज्य में सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान तैयार किये गए।

5. लोक वित्त अनुभाग

लोक वित्त अनुभाग प्रतिवर्ष निम्नलिखित दो रिपोर्ट तैयार करता है:–

(क) हरियाणा सरकार के बजट का आर्थिक एवं प्रयोजनवार वर्गीकरण

यह रिपोर्ट राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, केन्द्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपनाई गई पद्धति पर आधारित है। इस रिपोर्ट में हरियाणा सरकार के बजट का आर्थिक एवं प्रयोजनावर वर्गीकरण किया जाता है। सरकार के बजट में सामान्यतः व्यय का ब्यौरा विभागावार दिया जाता है ताकि इस पर वैधानिक नियंत्रण रखा जा सके, प्रशासकीय जवाबदेय हो तथा किसी भी प्रकार के खर्च का लेखा परीक्षण हो सके लेकिन सरकारी बजटीय लेन देन तभी अभिप्रायपूर्ण होता है जब उसे अर्थपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों जैसे उपभोग, व्यय, पूंजी निर्माण आदि में वर्गीकृत किया जाये तथा प्रयोजनवार वर्गीकरण में इन्हीं मदों को उनके प्रयोजन के अनुसार जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सेवाओं आदि में वर्गीकृत किया जाये। यह अनुभाग उक्त पद्धति के आधार पर राज्य के बजट के विश्लेशण द्वारा प्राप्त आंकड़े केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय को भेजता है जो इन आंकड़ों का प्रयोग राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में करते हैं। इन आंकड़ों का प्रयोग सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) तथा पूंजी निर्माण का अनुमान लगाने में भी किया जाता है।

(ख) राज्यों के वित्त विश्लेषण

इस रिपोर्ट में प्रयोग हुए डाटा को रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए बुलेटिन–स्टेट फाईनेन्सिज (बजटों का अध्ययन) से लिया जाता है। राज्यों के वित्त का विश्लेषण करते समय हरियाणा राज्य के बजट घटकों का दूसरे राज्यों के साथ तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। यह प्रकाशन विभिन्न पैरामीटर का प्रयोग करते हुए जैसे कि राज्यों को केन्द्र स्त्रोतों से प्राप्त आय, राज्यों के अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय और प्रति व्यक्ति प्राप्तियां, प्रति व्यक्ति विकास खर्चों, पूंजीगत आय और पूंजीगत खर्चे आदि भारत के सभी राज्यों के आय और व्यय से सम्बन्धित आधारभूत सांख्यिकी को दर्शाता है।

6. क्षेत्रीय लेखा अनुभाग

क्षेत्रीय लेखा अनुभाग हरियाणा राज्य की नगरपालिकाओं/परिषदों/निगमों के बजटों का आर्थिक तथा कार्यात्मक वर्गीकरण सम्बन्धी रिपोर्ट वार्षिक आधार पर तैयार करता है। इसके अतिरिक्त हरियाणा राज्य की ग्राम पंचायतों के बजट (खण्ड–वार) तथा पंचायत समितियों के बजटों की सूचना का एकत्रीकरण व संकलन कार्य करता है।

वर्ष 2014–15 के दौरान, हरियाणा राज्य की नगरपालिकाओं/परिषदों/निगमों के बजटों का आर्थिक तथा कार्यात्मक वर्गीकरण वर्ष 2012–13 से सम्बन्धित रिपोर्ट तैयार करके मुद्रित करवाई गई। इसके अतिरिक्त राज्य की सभी नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों तथा सभी ग्राम पंचायतों (खण्ड स्तर) के वर्ष 2013–14 के बजटों का एकत्रीकरण एवं संकलन कार्य भी प्रगति पर रहा।

7. कृषि अनुभाग

कृषि अनुभाग प्रति वर्ष दो रिपोर्ट नामतः "कृषि लेखा" एवं "कृषकों के परिवार बजट" तैयार करता है। कृषि लेखा में राज्य के चुने हुये कृषकों की जोतों की विभिन्न फसलों के उत्पादन, लागत तथा आय का अध्ययन किया जाता है। कृषकों के परिवार बजट अध्ययन के अन्तर्गत राज्य के चुने हुए कृषक परिवारों की आय तथा व्यय का विश्लेषण किया जाता है। अनुभाग द्वारा उक्त दोनों रिपोर्ट वर्ष 2012–13 की तैयार की गई व मुद्रित करवाई गई व वर्ष 2013–14 की रिपोर्ट से सम्बन्धित कार्य भी प्रगति पर रहा। इसके अतिरिक्त इस अनुभाग द्वारा नई सीरिज (आधार त्रैवर्षान्त 2007–08) के तहत विभिन्न फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन व ऊपज सूचकांक तैयार किये गये।

8. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण एवं सारणीकरण अनुभाग

यह अनुभाग भारत सरकार के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के सहयोग से क्षेत्रीय सर्वेक्षण का कार्य करता है। इस सर्वेक्षण के अन्तर्गत विभिन्न चरणों में भूमि उपयोगिता, ऋण तथा निवेश, विनिर्माण, घरेलू मकानों की दशा, उपभोक्ता व्यय तथा रोजगार एवं बेरोजगारी तथा व्यापार आदि कई सामाजिक–आर्थिक पहलुओं पर सूचना एकत्रित की जाती है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 71वें दौर (1 जनवरी, 2014 से 30 जून, 2014) का क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया तथा 72वें दौर (1 जुलाई, 2014 से 30 जून, 2015) का क्षेत्रीय सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर रहा। सभी सातों सर्कलों के 69वें व 70वें दौर के डाटा एंट्री एवं वेलिडेशन सम्बन्धी कार्य प्रगति पर रहा।

9. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अनुभाग

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक निश्चित अवधि के दौरान आधार वर्ष के संदर्भ में औद्योगिक उत्पादन की प्रवृति को दर्शाता है। औद्योगिक उत्पादन की प्रवृति के अध्ययन के लिए विनिर्माण, बिजली तथा खनन व उत्खनन क्षेत्रों के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार किया जाता है।

वर्ष 2014–15 के दौरान, इस अनुभाग द्वारा अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 के मासिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करने के साथ–साथ वर्ष 2006–07 से 2013–14 की वार्षिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक रिपोर्ट तैयार की गई।

10. प्रशिक्षण अनुभाग

यह अनुभाग विभिन्न विभागों के मध्यम/निचले स्तर के सांख्यिकीय कार्यों मे लगे कर्मचारियों के लिये जिला/राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। प्रशिक्षण का उद्देश्य इन कर्मचारियों को सांख्यिकी सम्बन्धित प्रारम्भिक ज्ञान जैसे आंकड़ों का एकत्रीकरण, संकलन, वर्गीकरण, सारणीकरण तथा प्रस्तुतीकरण आदि से परिचय करवाना है। प्रशिक्षणार्थियों को इस विभाग द्वारा इस दिशा में किये जा रहे कार्यों के बारे में भी अवगत कराया जाता है।

वर्ष 2014–15 में जिला स्तर पर तीन जिलों नामत्: झज्जर, मेवात व करनाल में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न विभागों के 109 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त विभाग के लगभग 96 अधिकारियों/कर्मचारियों को केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, श्रम ब्यूरो, भारत सरकार, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान, गुड़गांव, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद व अन्य संस्थानों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं में भाग लेने हेतु भेजा गया।

11. आर्थिक सर्वेक्षण अनुभाग

हरियाणा राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण, 2014–15 जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति दर्शाई जाती है, को तैयार कर बजट सत्र के दौरान हरियाणा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया।

12. सूचना प्रौद्योगिकी

यह अनुभाग विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों से सम्बन्धित कार्य करता है। अभी तक विभाग द्वारा सभी प्रकार के आंकड़ें मैन्युअल तौर पर एकत्रित/संकलित करने उपरान्त इनका विश्लेषण किया जाता है। मैन्युअल तौर पर आंकड़ें एकत्रित/संकलित करने में समय, श्रम एवं धन ज्यादा लगता है तथा महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों को तैयार करने मे अनावश्यक देरी भी होती है। अतः विभाग द्वारा आंकड़ें एकत्रित/संकलित करने की पूरी प्रक्रिया का कंप्यूटरीकरण करने की आवश्यकता महसूस हुई। विभाग ने इस कार्य के लिये आर.एफ.पी. द्वारा सिस्टम इन्टिग्रेटर की नियुक्ति की है। कंप्यूटरीकरण की इस पूरी परियोजना हेतु 3.97 करोड़ रूपये में विभाग ने व्याम टैक (सिस्टम इन्टिग्रेटर) को नियुक्त किया है। कंप्यूटरीकरण की यह प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् सभी प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़ों का सम्प्रेषण इलेकट्रोनिक माध्यम से हो सकेगा तथा और अधिक एडवांस विश्लेषण सम्भव हो सकेगा। विभाग के कंप्यूटरीकरण को दो चरणों में बाँटा गया।

प्रथम चरण में निम्नलिखित अनुभागों के लिए सॉफ्टवेयर डैवलोपमैंट का कार्य पूर्ण होने उपरान्त ऑनलाइन डाटा एन्ट्री का कार्य शुरू कर दिया गया है।

प्रथम चरण :–

(क) सांख्यिकीय विंग

1 कीमत

2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

3 लोक वित्त

4 संकलन (अमला के आंकड़ें)

5 राज्य आय

6 पूंजी निर्माण

7 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 68वां दौर

द्वितीय चरण में निम्नलिखित अनुभागों के लिए सॉफ्टवेयर डैवलोपमैंट का कार्य आरम्भ किया गया है ।

द्वितीय चरण :–

1 क्षेत्रीय लेखा

2 कृषि

3 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (डाटा एक्सपोर्ट)

4 संकलन (राज्य सांख्यिकीय सारांश)

5 राज्य योजना

13. तदर्थ सर्वेक्षण अनुभाग

यह अनुभाग विभिन्न प्रकार के तदर्थ सर्वेक्षण कार्य करता है। वर्ष 2014–15 के दौरान किये गए सर्वेक्षण कार्यों का विवरण निम्न अनुसार हैः–

राष्ट्रीय भवन संगठन

यह भी 100% केन्द्रीय प्रायोजित सर्वेक्षण है। इस सर्वेक्षण के तहत वर्ष 2007–08 से राज्य के सभी जिलों से नियमित तौर पर सूचना एकत्रित की जा रही है व भारत सरकार को ऑनलाइन भेजी जा रही है।

14. छठी आर्थिक गणना अनुभाग

आर्थिक गणना जो कि 7–8 वर्ष के अन्तराल पर की जाती है, के अन्तर्गत देश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित समस्त उधमों/इकाईयों की सम्पूर्ण गणना की जाती है। आर्थिक गणना के अन्तर्गत एकत्रित जानकारी योजना बनाने के प्रयोजनों हेतू महत्वपूर्ण है। भारत सरकार द्वारा 100% प्रायोजित छठी आर्थिक गणना स्कीम के अर्न्तगत क्षेत्रीय सर्वेक्षण का कार्य पूरे देश में जनवरी, 2013 से अप्रैल, 2014 के दौरान किया गया था। हरियाणा राज्य में छठी आर्थिक गणना के क्षेत्रीय सर्वेक्षण का कार्य मास फरवरी, 2013 में किया गया था। वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य में छठी गणना के क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य के अर्न्तगत भरे हुए प्रपत्रों की स्कैनिंग तथा 8 या इससे अधिक वर्कस वाले उद्यमों/इकाइयों की डायरेक्ट्री हेतु 6सी प्रपत्रों की डाटा एन्ट्री इत्यादि का कार्य प्रगति पर रहा। इसके अतिरिक्त छठी आर्थिक गणना के अन्नतिम परिणाम जारी किये गए।

15. स्टेट स्ट्रैटेजिक सांख्यिकीय प्रोजेक्ट अनुभाग

सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में सांख्यिकीय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु यह परियोजना आरम्भ की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया जाना है जिसे तैयार करने का कार्य प्रगति पर रहा।

(ख) योजना विंग

16. योजना निरूपण अनुभाग

यह अनुभाग राज्य की पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना तैयार करने सम्बन्धी कार्य करता है। वर्ष 2015–16 की राज्य की प्रस्तावित योजना तैयार करने हेतु विभिन्न विभागों से उनके प्रस्ताव मंगवाकर संकलित किये गये तथा प्रस्तावित परिव्यय निर्धारित कर विभागों को सूचित किया गया।

वार्षिक योजना 2014–15 का परिव्यय संशोधित कर विभागों को सूचित किया गया। विभिन्न विभागों से वार्षिक योजना 2014–15 से सम्बन्धित अतिरिक्त परिव्यय/आपस में स्कीमों या राशि के परिवर्तन के लिए प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा उपरान्त विभागों को आवश्यक परामर्श जारी किये गये।

विभिन्न विभागों से प्राप्त नई परियोजनाओं की समीक्षा करने उपरान्त स्टैन्डिंग फाईनैन्स कमेटी की मीटिंग हेतु दस्तावेज तैयार किये गये।

फिस्कल पोलिसी संस्थान, बैंगलोर की तर्ज पर हरियाणा में भी एक संस्थान स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर हरियाणा सरकार को प्रस्तुत की गई।

केन्द्रीय बजट 2015–16 हेतू राज्य सरकार के विचार भारत सरकार को भेजे गये।

17. योजना मोनिटरिंग अनुभाग

यह अनुभाग राज्य योजनाओं, विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों/परियोजनाओं तथा फ्लैगशिप कार्यक्रमों की प्रगति की मोनिटरिंग हेतु रिपोर्ट एकत्रित/संकलित करने का कार्य करता है।

इस अनुभाग द्वारा वार्षिक योजना 2013–14 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट व वार्षिक योजना 2014–15 की प्रथम (30–06–2014), द्वित्तीय (30–09–2014) व तृतीय (31–12–2014) तिमाही की वित्तीय व भौतिक प्रगति रिपोर्ट एकत्रित व संकलित करके योजना आयोग, भारत सरकार एवं सम्बन्धित विभागों को प्रेषित की गई। वर्ष 2014–15 के फ्लैगशिप कार्यक्रमों की प्रथम (30–06–2014), द्वितीय (30–09–2014) व तृतीय (31–12–2014) तिमाही की वित्तीय व भौतिक प्रगति सम्बन्धित रिपोर्ट एकत्रित व संकलित करने उपरान्त नीति आयोग, भारत सरकार एवं सम्बन्धित विभागों को प्रेषित की गई।

18. योजना मूल्यांकन अनुभाग

यह अनुभाग विकास कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के मूल्यांकन/अध्ययन सम्बन्धी कार्य करता है।

वर्ष 2014–15 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा इस कार्य हेतु चयनित दो संस्थाओं ने 8 निम्नलिखित मूल्यांकन/अनुसन्धान ड्राफट रिर्पोटें प्रस्तुत की जिन्हें हाई पॉवर कमेटी से अनुमोदित करवाने का कार्य प्रगति पर रहा :–

1 (क) अध्यापकों एवं विद्यालयों के मुखियाओं के कार्य प्रबन्धन एवं अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरणा देने के तरीकों की पहचान करना, उपस्थिति सुनिश्चित करना और अध्यापन समय का सदुपयोग करना इत्यादि।

(ख) विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम करना/उन्हें स्कूल में रखना।

(ग) सरकारी विद्यालयों को वरीयता क्यों नहीं दी जाती।

2 कृषि क्षेत्र में बढ़ती अनावश्यक बिजली रियायतों की समीक्षा।

3 राज्य में महिला एवं बाल उत्पीड़न रोकने के लिए उठाये गए कदमों की समीक्षा।

4 वर्तमान में नागरिकों की संतुष्टि के स्तर का मूल्यांकन।

5 सामान्य सेवायें : सेवायें प्रदान करने का संस्थागत ढाँचा।

6 सामान्य सेवा प्रक्रिया, तौर तरीके एवं सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया का मूल्यांकन।

7 अर्न्तक्षेत्रीय असमानता दूर करने के लिए नीति निर्धारण।

8 राज्य सरकार द्वारा मेवात के निवासियों की असमानताऐं दूर करने हेतु उठाये गए कदमों के प्रभाव का आंकलन।

19. जिला योजना अनुभाग

इस अनुभाग द्वारा जिला योजना स्कीम के कार्यान्वयन सम्बन्धी दिशा निर्देश जारी करने तथा अनुमोदित जिला योजनाओं अनुसार विकास कार्य करवाने हेतु सभी जिलों को राशि आबंटित/जारी करने का कार्य किया जाता है। वर्ष 2014–15 के दौरान, जिला योजना स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा 30,750.00 लाख रुपये की राशि अनुमोदित की गई। राज्य सरकार द्वारा माह जनवरी 2015 में इस राशि में से 10,000.00 लाख रुपये की राशि जिलों की जनसंख्या अनुसार जारी की गई तथा इस राशि को उपयोग करने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गए।

जिला योजना स्कीम वर्ष 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13 तथा 2013–14 से सम्बन्धित 31.03.2014, 30.06.2014, 31.12.2014 तथा 31.03.2015 त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों व उपयोगिता प्रमाण पत्रों के संकलन का कार्य प्रगति पर रहा।

20. मानवशक्ति तथा रोजगार समन्वय अनुभाग

मानवशक्ति तथा रोजगार समन्वय अनुभाग विशेष कार्य अधिकारी (मानवशक्ति) के अधीन कार्य करता है। इस अनुभाग का मुख्य कार्य तकनीकी व्यक्तियों जैसे कि डाक्टर, अभियन्ता, अध्यापक तथा कृषि विशेषज्ञों की मांग तथा पूर्ति सम्बन्धित अनुमान लगाना है। योजना स्कीमों के अधीन रोजगार तथा बेरोजगारी सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन इसी अनुभाग द्वारा किया जाता है। रोजगार विभाग, हरियाणा से राज्य में रोजगाार की स्थिति, बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा रोजगार के लिए नाम दर्ज करवाने वालों तथा तकनीकी योग्यता निपुण रोजगार चाहने वालों की संख्या आदि सूचनाओं को एकत्रित करने का कार्य प्रगति पर रहा। इसके अतिरिक्त गरीबी उन्मूलन रोजगार कार्यक्रम, स्व-रोजगार स्कीम एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) तथा वार्षिक योजना 2014–15 के अन्तर्गत विभिन्न स्कीमों के तहत उपलब्ध करवाये गए रोजगार बारे सूचना एकत्रित करने का कार्य भी प्रगति पर रहा।

21. प्रदर्शन प्रबन्धन सैल अनुभाग

वर्ष 2014–15 के लिये आर0एफ0डी0 से सम्बन्धित 40 विभागों से आर0एफ0डी0 की सूचना वेबसाईट पर अपलोड करवाई गई। इस विभाग के सभी अनुभागों से वर्श 2013–14 की उपलब्धियों तथा वर्ष 2014–15 की आर0एफ0डी0 से सम्बन्धित सूचना एकत्रित करके वर्ष 2014–15 के लिए विभाग की आर0एफ0डी0 तैयार की गई तथा उसे वेबसाईट पर अपलोड किया गया। सम्बन्धित विभागों से वेबसाइट पर प्राप्त सूचना का संकलन करके वर्ष 2014–15 की आर0एफ0डी0 का डाक्यूमैंट तैयार किया गया तथा मुद्रित करवाई गई। इसके अतिरिक्त विभागों से वित्त वर्ष 2013–14 की उपलब्धियों को भी आर0एफ0डी0 की वेबसाइट पर अपलोड करवाया गया।

(ग) जिला सांख्यिकीय कार्यालय

राज्य के सभी 21 जिलों में जिला सांख्यिकीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं। जिला सांख्यिकीय कार्यालयों के मुख्य कार्य संक्षिप्त रूप से नीचे वर्णित हैं :–

(क) जिले की आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों पर सभी प्रकार के आंकड़ों का संग्रह/संकलन उपरान्त इनका प्रेषण मुख्यालय को करना।

(ख) जिलों में किये जाने वाले विभिन्न सर्वेक्षणों में सहायता करना।

(ग) आंकड़े प्रदान करने वाली अन्य एजैन्सियों को इनके संग्रह तथा संकलन कार्य के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन प्रदान करना।

(घ) जिला स्तर के विभिन्न कार्यालयों में सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय करना।

जिला सांख्यिकीय कार्यालयों द्वारा की जाने वाली नियमित सांख्यिकीय गतिविधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(अ) जिला सांख्यिकीय सारांश

जिला सांख्यिकीय कार्यालय जिला स्तर पर विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक पहलुओं पर आंकड़ों का संग्रह तथा संकलन करने वाली प्रमुख एजैन्सी है। इस विषय पर मुख्य प्रकाशन जिला सांख्यिकीय सारांश है जिसमें सभी प्रकार के जिला स्तरीय आंकड़ों का समावेश होता है। वर्ष 2014–15 के दौरान, जिला सांख्यिकीय सारांश 2012–13 सभी जिला सांख्यान कार्यालयों द्वारा तैयार किये गये।

(आ) कीमत सम्बन्धी आंकड़े

जिला सांख्यिकीय कार्यालय मार्किट कमेटियों से कृषि उत्पादों की थोक कीमतें, जिला मुख्यालय नगरों से खुदरा भाव तथा चुने हुए बाजारों तथा औद्योगिक कस्बों से परचून कीमतें एकत्रित कर इनका प्रेषण मुख्यालय को करते हैं। इन आंकड़ो का प्रयोग राज्य स्तर के सूचकांक तैयार करने के लिए किया जाता है।

(इ) मण्डी आमद

जिला सांख्यिकीय कार्यालयों द्वारा विभिन्न कृषि उत्पादों के मण्डी आमद सम्बन्धी आंकड़े भी मार्किट कमेटियों से एकत्रित किये जाते हैं।

(ई) **नगरपालिका वार्षिक पुस्तक**

नगरपालिका वार्षिक पुस्तक में प्रत्येक जिले की नगरपालिकाओं के क्षेत्रफल, जनसंख्या, नगरपालिका के व्यवसाय, चिकित्सा, शिक्षा एवं अन्य सामाजिक तथा आर्थिक पहलुओं के महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं। शहरी स्तर की सामाजिक तथा आर्थिक सूचना के लिये यह प्रकाशन बहुत उपयोगी है। वर्ष 2014–15 के दौरान नगरपालिका वार्षिक पुस्तक वर्ष 2012–13 सभी जिला सांख्यान कार्यालयों द्वारा तैयार की गई।

(उ) **20 सूत्रीय कार्यक्रम**

राज्य में चल रहे 20–सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्टों का उपायुक्तों एवं जिला स्तरीय पुनर्निरीक्षण समितियों द्वारा पुनर्निरीक्षण प्रत्येक माह करवाया गया तथा वांछित सूचना मुख्यालय को भी प्रेषित की गई।

(ऊ) **जिला सामाजिक आर्थिक पुनर्निरीक्षण**

जिला सामाजिक आर्थिक पुनर्निरीक्षण, 2012–13 जिसमें जिला स्तर के विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों से सम्बन्धित आंकड़ों का संक्षिप्त विवरण है, सभी जिलों द्वारा तैयार किये गये।

(घ) जिला योजना कार्यालय

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई विकेन्द्रीकृत योजना के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा सभी जिलों में जिला योजना कार्यालय खोले गये थे। सम्बन्धित जिलों के अतिरिक्त उपायुक्त इन कार्यालयों में मुख्य योजना एवं विकास अधिकारी के रूप में बतौर कार्यालय अध्यक्ष कार्य करते हैं। वर्ष 2007–08 में विकेन्द्रीकृत योजना को समाप्त कर जिला योजना नामक नई स्कीम शुरू की गई है। ये कार्यालय अपने–अपने जिलों में स्थानीय स्तर के विकास के लिए जिले की जिला योजना बनाकर इनका अनुमोदन जिला विकास एवं मोनिटरिंग कमेटी से अनुमोदित करवाने का कार्य करते हैं। इसके पश्चात् विभाग द्वारा जिला योजना स्कीम के अर्न्तगत जारी की गई राशि विभिन्न विकास कार्यों को करवाने के लिए कार्यान्वयन एजैन्सियों को जारी करते हैं। वर्ष 2014–15 में विभिन्न जिलों की योजनाओं के अनुमोदन के लिये तथा पूर्व में जारी राशि से किये गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिये जिला योजना समितियों की बैठकों का नियमित रूप से आयोजन करवाया गया।

(ङ) चौकसी से सम्बन्धित सूचना

चौकसी विभाग द्वारा वर्ष 2014–15 में इस विभाग से सम्बन्धित कोई मामला नोटिस में नहीं लाया गया।

***

अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा के राजपत्रित तथा अराजपत्रित वर्ग के पदों का विवरण 2014–15 (31–3–2015 की स्थिति अनुसार)

मुख्यालयः

पद संज्ञा	पदों की संख्या		
	स्वीकृत पद	भरे हुये पद	रिक्त पद
राजपत्रित			
निदेशक	1	1	–
अतिरिक्त निदेशक	2	2	–
संयुक्त निदेशक	2+1*	1	1+1*
उप निदेशक	10	9	1
अनुसंधान अधिकारी	31	26+1@	4
अधीक्षक	1	–	1
लेखा अधिकारी	1	1	–
अराजपत्रित			
सहायक अनुसंधान अधिकारी/छानबीन निरीक्षक	47+2*	37+1@	9+2*
सांख्यिकीय सहायक/निरीक्षक (र0प0स0)/अन्वेषक	17+3*	9	8+3*
क्षेत्रीय सहायक	19	13	6
अवर क्षेत्रीय अनुसंधाता	8+2*	3	5+2*
कलाकार एवं प्रारूपकार	1	1	–
उप अधीक्षक	2	2	–
सहायक	14	14	–
निजी सहायक	2	–	2
वरिष्ठ आशुलिपिक	6	6	–
कनिष्ठ आशुलिपिक	7+1*	3	4+1*
आशुटंकक	20	8	12
लिपिक	13	4	9
चालक	4	3	1
मशीन आपरेटर (डुप्लीकेटिंग मशीन)	1	–	–
मशीन आपरेटर (फोटोस्टेट मशीन)	1	–	–
सेवक	32	9+1@	22

जिला सांख्यान कार्यालयः

राजपत्रित	स्वीकृत पद	भरे हुये पद	रिक्त पद
जिला सांख्यान अधिकारी	21	19	2
अराजपत्रित			
सहायक जिला सांख्यान अधिकारी	21	21	—
सांख्यिकीय सहायक/निरीक्षक (र0प0स0)/अन्वेशक	27	18	9
क्षेत्रीय सहायक	48	35	13
अवर क्षेत्रीय अनुसंधाता	40	7	33
अनुरेखक	—	3**	——
सहायक	21	17+2[@]	2
लिपिक	19	12	7
सेवक	40	24	16

जिला योजना कार्यालयः

राजपत्रित	स्वीकृत पद	भरे हुये पद	रिक्त पद
मुख्य योजना तथा विकास अधिकारी	19[#]	—	अतिरिक्त उपायुक्त कार्यभार
योजना अधिकारी	21	20	1
अराजपत्रित			
सहायक योजना अधिकारी	21	21	—
कार्टोग्राफर	—	10**	—
मशीन आपरेटर	—	2	—
सेवक	21	12	9
कुल योग	**542+19[#]+9***	**360+13**+5[@]**	**177+9***

[@] कर्मचारी अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

* आर्थिक गणना स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत पद।

** अधिक भरे गये पद विभाग की रीस्ट्रक्चरिंग/राईट साईजिंग के कारण हैं तथा ये पद डिमीनिशींग/डाईंग कैडर में रखे गये हैं।

[#] अतिरिक्त तौर पर कार्यभार अतिरिक्त उपायुक्त के पास है।

सांख्यिकीय दिवस का आयोजन

केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार के निर्णय अनुसार विभाग द्वारा 29 जून, 2014 को प्रोफेसर महलानोबिस के जन्मोत्सव को सांख्यिकीय दिवस के रूप मे मनाया गया तथा इस उपलक्ष पर एक वर्कशाप का आयोजन किया गया। इस वर्कशाप की विषय वस्तु "सेवा क्षेत्र सांख्यिकी" थी। इस वर्कशाप में औद्योगिक एवं ग्रामीण विकास अनुसंधान केन्द्र, चण्डीगढ़ तथा गुरू जम्भेश्वर विश्वविधालय, हिसार के 3 सांख्यिकीय विशेषज्ञों को व्याख्यान देने के लिए आमन्त्रित किया गया था। इस अवसर पर विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के मुख्यालय स्थित सांख्यिकीय खण्डों से सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे।

श्री राजन गुप्ता, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव, योजना विभाग ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में आंकड़ों की गुणवता एवं महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने आंकड़ों की गुणवता को बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव भी दिये। इस अवसर पर निदेशक, अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग ने इस विभाग द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों के सन्दर्भ में अवगत कराया। इस अवसर पर नवीनतम आंकड़ों को कम से कम समय में उपलब्ध करवाने हेतू सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व पर भी चर्चा की गयी। इस अवसर पर सभी उपस्थित सदस्यों ने आंकड़ों की गुणवता सुनिश्चित करने का संकल्प भी लिया।

*****

श्री राजन गुप्ता, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव, योजना विभाग दीप प्रजवल्लीत कर सांख्यिकीय दिवस समारोह का शुभारम्भ करते हुए

श्री राजन गुप्ता, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव, योजना विभाग सांख्यिकीय दिवस पर अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए

योजना भवन, पंचकूला

अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग, हरियाणा का मुख्यालय भवन